Current Affairs search results for tag: economicsbusiness

1. टाइटन एसबीआई कार्ड लॉन्च: विशेष लाभ और आसान नामांकन (March 23, 2024)

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने टाइटन एसबीआई कार्ड का अनावरण करने के लिए टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो सालाना ₹2,00,000 के विशेष लाभ प्रदान करता है।

खबर का अवलोकन

- ₹2,999 की मामूली ज्वाइनिंग फीस के साथ, उपयोगकर्ताओं को टाइटन ब्रांडों से खरीदारी पर 7.5% का उदार कैशबैक मिलता है।

नामांकन विकल्प

- डिजिटल सुविधा: नामांकन में आसानी सुनिश्चित करते हुए व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट पर एसबीआई कार्ड स्प्रिंट के माध्यम से डिजिटल रूप से टाइटन एसबीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इन-स्टोर पहुंच: नामांकन टाइटन स्टोर्स पर भी उपलब्ध है, जो संभावित कार्डधारकों को पहुंच प्रदान करता है।

फीस और प्लेटफार्म

- किफायती शुल्क: टाइटन एसबीआई कार्ड में ₹2,999 का मामूली जुड़ाव और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क शामिल है, जो इसे उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बनाता है।
- भुगतान बहुमुखी प्रतिभा: RuPay और VISA दोनों भुगतान प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक स्वीकृति और सुविधा सुनिश्चित करता है।

कैशबैक लाभ

- विशेष पुरस्कार: टाइटन की घड़ियाँ, तनीरा की महिलाओं के जातीय परिधान, टाइटन आईप्लस के आईवियर और अन्य गैर-आभूषण टाइटन ब्रांडों से खरीदारी पर आकर्षक 7.5% कैशबैक का आनंद लें।
- पार्टनर स्टोर के लाभ: मिया, कैरेटलेन और ज़ोया जैसे पार्टनर स्टोर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदारी करने पर आकर्षक 5% कैशबैक का लाभ उठाएं।

उपहार वाउचर पुरस्कार

- उन्नत खरीदारी अनुभव: तनिष्क आउटलेट्स पर की गई खरीदारी के लिए लेनदेन मूल्य के 3% मूल्य के टाइटन उपहार वाउचर अर्जित करें, जो आपके खरीदारी अनुभव को और समृद्ध करेगा।

2. ग्रिड-इंडिया ने मिनीरत्न मान्यता प्राप्त की (March 21, 2024)

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) ने मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) का दर्जा प्राप्त किया।

खबर का अवलोकन

- भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय ग्रिड-इंडिया को मिनीरत्न श्रेणी-I की मान्यता प्रदान करता है।
- यह स्थिति देश के बिजली क्षेत्र में ग्रिड-इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में ग्रिड-इंडिया की उन्नत स्थिति का प्रतीक है।

ग्रिड-इंडिया के बारे में

- 2009 में स्थापित, ग्रिड-इंडिया को भारतीय विद्युत प्रणाली के सुचारू संचालन की देखरेख का काम सौंपा गया है।
- इसके प्राथमिक कर्तव्यों में क्षेत्रों के भीतर और पार कुशल बिजली हस्तांतरण सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय बिजली आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर जोर देना शामिल है।
- ग्रिड-इंडिया प्रतिस्पर्धी और कुशल थोक बिजली बाजारों को बढ़ावा देने और निपटान प्रणालियों को प्रशासित करने में भी भूमिका निभाता है।
- इसमें पांच क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) शामिल हैं।
- ग्रिड-इंडिया अखिल भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड का प्रबंधन करता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल बिजली प्रणालियों में से एक है।

ज्ञान-संचालित ऑपरेशन:

- ग्रिड-इंडिया एक ज्ञान-संचालित इकाई के रूप में कार्य करती है, जो बिजली क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करते हुए भारत सरकार द्वारा अनिवार्य विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रमुख आदेश और कर्तव्य:

- ग्रिड-इंडिया की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
    - निर्बाध बिजली प्रणाली संचालन की देखरेख करना,
    - क्षेत्रों के भीतर और पार कुशल बिजली हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना,
    - अंतरराष्ट्रीय बिजली आदान-प्रदान को सक्षम करना,
    - अखिल भारतीय सिंक्रोनस ग्रिड का प्रबंधन करना
    - प्रतिस्पर्धी थोक बिजली बाजारों को बढ़ावा देना

  - निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करना
  - सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय सुनिश्चित करना
  - राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली संचालन

उन्नत मान्यता:

- विद्युत मंत्रालय से मिनीरत्न श्रेणी-I सीपीएसई का दर्जा प्राप्त करना भारत के विद्युत परिदृश्य में ग्रिड-इंडिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन, परिचालन दक्षता और रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।
- यह मान्यता ग्रिड-इंडिया को परिचालन स्वायत्तता को और बढ़ाने, उभरते बाजार की गतिशीलता को नेविगेट करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनाती है।

3. राष्ट्रपति ने पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया (Sept. 21, 2023)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 सितंबर, 2023 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन

- उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी सहित प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।
- ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक चलेगा और इसमें **ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स** और **ई-कॉमर्स** जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 2000 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे।
- राज्य सरकार के विभाग, संस्थान और मुंबई डब्बावाला सेवा व्यावसायिक गतिविधियों पर जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित करेंगे।
- यह आयोजन **108 नए स्टार्टअप का प्रदर्शन** करेगा।
- इसमें अंतरराष्ट्रीय उपस्थित लोगों सहित पांच लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है।

कार्यक्रम का स्थान और वैश्विक भागीदारी:

- ट्रेड शो **ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क** में **इंडिया एक्सपो मार्ट** में होगा।
- इस आयोजन का उद्देश्य **अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन हासिल करने और बाजार के अवसरों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के उत्पादों, विशिष्टताओं, व्यंजनों और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।**

- 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय अपील को उजागर करता है। शो में आम जनता का प्रवेश निःशुल्क है।

4. आईआरईडीए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की (Sept. 20, 2023)

आईआरईडीए (भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से साझेदारी की।

खबर का अवलोकन

- प्राथमिक लक्ष्य **पूरे भारत में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह-उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।**

- यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के भारत के प्रयासों का समर्थन करती है।

- एमओयू पर औपचारिक रूप से **आईआरईडीए के महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) भरत सिंह राजपूत और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक (खुदरा और एमएसएमई क्रेडिट) राजेश सिंह** ने नई दिल्ली में आईआरईडीए के बिजनेस सेंटर में हस्ताक्षर किए।

सतत ऊर्जा अवसंरचना:

- सहयोग का लक्ष्य **हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियादी ढांचा स्थापित करना है।**

- यह बुनियादी ढांचा विभिन्न समुदायों और उद्योगों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों तक पहुंच बढ़ाएगा।

सरकारी लक्ष्यों के साथ संरेखण:

- यह साझेदारी वित्तीय संस्थानों और सरकारी निकायों के एक साथ काम करने के महत्व को रेखांकित करती है।

- यह संरेखण माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है।

एमओयू में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं:

- सह-ऋण और सह-उत्पत्ति सहायता।

- ऋण सिंडिकेशन और अंडरराइटिंग सुविधा

- पारदर्शिता के लिए ट्रस्ट एवं रिटेंशन खातों का प्रबंधन।

- 3-4 वर्षों में आईआरईडीए उधारों के लिए स्थिर निश्चित ब्याज दरें।

आईआरईडीए के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक - **प्रदीप कुमार दास**

5. इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 'आईबी साथी' पहल शुरू की (Sept. 18, 2023)

इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन की दिशा में अपने प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से 'आईबी साथी' (समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी) नामक एक नई पहल शुरू की।

खबर का अवलोकन

- इस पहल के हिस्से के रूप में, इंडियन बैंक अपने सभी केंद्रों पर निश्चित आउटलेट के माध्यम से हर दिन कम से कम चार घंटे बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- निश्चित आउटलेट्स के अलावा, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) एजेंट भी ग्राहकों के दरवाजे पर सीधे अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

विस्तार योजनाएँ:

- इंडियन बैंक की अपने बीसी नेटवर्क का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं।
- मार्च 2024 तक, बैंक का लक्ष्य 5,000 से अधिक नए बीसी तैनात करने का है।
- वर्तमान में, इसके पास पहले से ही 10,750 बीसी और 10 कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (सीबीसी) हैं, और यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 15,000 बीसी और 15 सीबीसी हो जाएगी, जिससे बैंक की पहुंच और कवरेज का विस्तार होगा।

सेवा पोर्टफोलियो:

- इंडियन बैंक वर्तमान में अपने बीसी चैनल के माध्यम से ग्राहकों को 36 विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। हालाँकि, आने वाले वर्षों में, बैंक का इरादा FY25 तक अतिरिक्त 60 सेवाएँ शुरू करने का है।
- सेवाओं का यह विस्तार ग्राहकों को सशक्त बनाएगा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा।

6. एसबीआई ने 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' लॉन्च किया (Sept. 9, 2023)

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आवागमन के अनुभवों को बेहतर बनाने और डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' लॉन्च किया।

खबर का अवलोकन

- नवोन्मेषी 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' का लक्ष्य **मेट्रो, बसों, वॉटर फ़ेरी, पार्किंग और अन्य सहित विभिन्न परिवहन साधनों के लिए एक ही कार्ड के भीतर डिजिटल टिकट किराया भुगतान को सरल बनाना है।**
- परिवहन भुगतान के अलावा, **कार्ड का उपयोग खुदरा और ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है।**
- 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' **RuPay** और **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)** तकनीक द्वारा संचालित है, जो इसे लाखों भारतीयों के लिए उनके दैनिक आवागमन में एक संभावित गेम-चेंजर बनाता है।

एसबीआई की एनसीएमसी सुविधा:

- एसबीआई की एनसीएमसी सुविधा उसके ग्राहकों को उन क्षेत्रों में मेट्रो रेल और बसों में यात्रा कार्ड के रूप में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाती है जहां यह सेवा उपलब्ध है।
- एनसीएमसी **RBI द्वारा गठित नंदन नीलेकणि समिति** द्वारा प्रस्तावित।
- इसका उद्देश्य **कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देना और कम्यूटर भुगतान को एकीकृत करना है।**
- एनसीएमसी को **4 मार्च, 2019** को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।
- एनसीएमसी RuPay प्लेटफॉर्म पर काम करती है, जिसे **नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** द्वारा विकसित किया गया था।
- एनसीएमसी संपूर्ण संपर्क रहित परिवहन समाधान प्रदान करता है और यह एक स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- यह **मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे के लिए भुगतान की अनुमति** देता है।

एसबीआई के अध्यक्ष - दिनेश कुमार खारा

7. भारत में टोकनयुक्त कार्डों के लिए वीज़ा ने सीवीवी-मुक्त भुगतान की शुरुआत की (May 6, 2023)

Visa introduces CVV-free payments for tokenized cards in India

वीजा ने भारत में एक नई सुविधा **सीवीवी-मुक्त भुगतान** शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को सीवीवी नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है।

खबर का अवलोकन

- यह सुविधा **टोकनयुक्त क्रेडिट और डेबिट कार्ड** पर लागू है और केवल भारत में घरेलू लेनदेन के लिए उपलब्ध है।

- कार्ड को एक **अद्वितीय कोड** के साथ सुरक्षित करके टोकन किया जाता है और दो-कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके लेनदेन पूरा किया जाता है, जिसके लिए 16-अंकीय कार्ड नंबर या किसी अन्य कार्ड विवरण की आवश्यकता नहीं होती है।
- टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सुनिश्चित करती है कि नया ऑथेंटिकेशन मेथड यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाता है क्योंकि टोकन का इस्तेमाल दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकता है।

टोकनाइजेशन के बारे में

- यह एक सुरक्षा प्रक्रिया है जो संवेदनशील डेटा को अद्वितीय कोड के साथ बदल देती है जिसे टोकन कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य संवेदनशील डेटा को साइबर हमलों और धोखाधड़ी से बचाना है।
- ऑनलाइन लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए भुगतान उद्योग में टोकनाइजेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जहां संवेदनशील डेटा को विभिन्न पक्षों के बीच साझा करने की आवश्यकता होती है।

वीज़ा इंक के बारे में

- यह एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है।
- कंपनी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित है।
- वीज़ा इंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड सहित अपने विभिन्न भुगतान उत्पादों के माध्यम से विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है।
- स्थापना - **18 सितंबर, 1958**
- संस्थापक - **डी हॉक**
- मुख्यालय - **सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यू.एस.**

8. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की करेंगे अगवानी (May 6, 2023)

Minister Sarbananda Sonowal to receive first Indian cargo ship at Sittwe port

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री **सर्बानंद सोनोवाल** 9 मई को **म्यांमार के सितवे बंदरगाह** पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी करेंगे।

खबर का अवलोकन

- सिटवे पोर्ट **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा** है और इसका विकास दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मल्टी-मोडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा।
- बंदरगाह का निर्माण भारत और म्यांमार के बीच कलादान नदी पर **एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट** सुविधा स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा समझौते के तहत किया गया है, जो म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत में मिजोरम से जोड़ता है।
- कलादान नदी मार्ग में बंगाल की खाड़ी के पूरे प्रायद्वीप के लिए आर्थिक अवसरों को खोलने की क्षमता है।

म्यांमार के बारे में

- यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है।
- म्यांमार की राजधानी शहर नैप्यीडॉ है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2005 में राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
- अध्यक्ष - **म्यिंट स्वे (कार्यवाहक)**
- SAC के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री - **मिन आंग हलिंग**
- SAC के उपाध्यक्ष और उप प्रधान मंत्री - **सो विन**

9. केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे (April 17, 2023)

केंद्रीय इस्पात मंत्री **ज्योतिरादित्य सिंधिया** 19 अप्रैल को **मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023** का उद्घाटन करेंगे।

खबर का अवलोकन

- **केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग** से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कर रहा है।

- इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19-21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी।

- इस आयोजन का **मुख्य उद्देश्य** इस्पात उद्योग में नवीनतम विकास, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।

- इंडिया स्टील 2023 प्रदर्शनी भारतीय इस्पात उद्योग की **उन्नत तकनीकों, उत्पादों और समाधानों** का प्रदर्शन करेगी।

- यह **द्विवार्षिक कार्यक्रम** उपस्थित लोगों को उद्योग के नेताओं के साथ जुड़ने, भविष्य की विकास संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और भारतीय इस्पात उद्योग में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता।

सत्रों के विषय

- लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने का विस्तार।

- भारतीय इस्पात उद्योग के लिए मांग गतिशीलता।

- ग्रीन स्टील के माध्यम से स्थिरता लक्ष्य: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता।

- भारतीय इस्पात के लिए अनुकूल नीतिगत ढांचा और प्रमुख सहायक।

- उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)

- यह भारत के शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक **व्यापारिक लॉबी समूह** है जिसकी **स्थापना घनश्याम दास बिड़ला** ने की थी।
- इसकी **स्थापना 1927** में हुई थी
- यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यापार के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
- मुख्यालय: **नई दिल्ली**
- अध्यक्ष: **सुब्रकांत पांडा**

10. रक्षा मंत्रालय 2022 में MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीददार बना (Jan. 31, 2023)

हाल ही में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि 2022 में, रक्षा मंत्रालय MSME विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा।

खबर का अवलोकन

- 2022 में, **रक्षा मंत्रालय ने MSME क्षेत्र से 16,747 करोड़ रुपये के सामान और सेवाओं की खरीदारी की।** यह 2021 में की गई खरीद से 250% अधिक थी।
- राज्यों में **उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक खरीद की। उत्तर प्रदेश ने GeM के माध्यम से 9,642 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की।**

2022 में GeM का कारोबार

- **2022 में GeM का टर्नओवर 1,06,647 करोड़ रुपए रहा** जो 2023 में दोगुना होने की उम्मीद है।
- 2016 की तुलना में, जब GeM पहली बार लॉन्च किया गया था, तब से इसके कारोबार 17 गुना वृद्धि हुई है।

गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म

- लॉन्च - 9 अगस्त 2016
- उद्देश्य - सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाना
- नोडल मंत्रालय - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- GeM समावेश, पारदर्शिता और दक्षता पर काम करता है

- GeM पर किसका पंजीकरण होता है - कारीगर, बुनकर, एसएचजी, स्टार्टअप, महिला उद्यमी और एमएसएमई पंजीकृत हैं।